OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE (SOUTH-WEST)
DWARKA COURTS, NEW DELHI.

NOTICE

In accordance with letter No. F.No. 6/12/2018-Judl/jtsecylaw/820-830, dated 02nd July, 2024, received from the Department of Law, Justice and Legislative Affairs, Delhi Secretariat, Government of National Capital Territory of Delhi, a copy of the gazette notification dated 14th June, 2024, notifying the "Appointment of Official Receivers for National Capital Territory of Delhi Rules, 2024" has been forwarded to this office. A panel of five advocates is to be recommended for the selection of one as the Official Receiver under Section 57 of the Provincial Insolvency Act, 1920.

Applications are invited from eligible advocates, as per the criteria outlined in the attached notification, for the appointment of Official Receiver. The prescribed proforma (copy enclosed) must be used, and applications, complete in all respects, must be submitted in a sealed envelope addressed to the Ld. Principal District & Sessions Judge (South-West), Dwarka Courts, New Delhi. The envelope should be delivered to the R & I Branch (5th floor), Administrative Block, Dwarka Courts, latest by **05:00 PM** on **10.07.2024.**

No applications or representations received after the specified date and time will be considered or entertained under any circumstances.

(Vikas Dhull)
District Judge (Commercial Court)-02,
Dwarka District Courts, New Delhi.

No. 21468-471 /Official Receiver/Genl./DWK/2024. Dated: 05-07-2024

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The President/Hony. Secretary of Dwarka Courts Bar Association, Dwarka Courts (with the request to get this notice displayed on their respective webpage, notice boards, as well as to circulate the same in the WhatsApp groups of its members, and also through bulk SMS services, if any).
2. The Ld. Principal District and Sessions Judge's Secretariat, Dwarka Courts.
3. The Branch Incharge, Computer Branch, Dwarka Courts (for getting this notice uploaded on web pages of Dwarka Courts Complex/ Delhi District Courts).
4. The Caretaker, Caretaking Branch, Dwarka Courts (for getting this notice displayed on all the notice boards of Dwarka Court Complex).

(Vikas Dhull)
District Judge (Commercial Court)-02,
Dwarka District Courts, New Delhi.

PERFORMA FOR APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF OFFICIAL RECEIVER U/S 57 OF THE PROVINCIAL INSOLVENCY ACT, 1920, AT DWARKA COURTS COMPLEX.

Latest Colour Photo of the Applicant

1.	Name of the Applicant	
2.	Father's/Husband's Name	
3.	Date of Birth	
4.	Enrollment No. and date of enrollment as an Advocate with Bar Council of Delhi. **(Attach copy of Enrollment Certificate)**	
5.	Total standing at the Bar (in years)	
6.	Name of Bar Association/s with which registered alongwith Membership Number/s.	
7.	Residential Address	
8.	Official Address	
9.	Contact Nos.	
10.	E-mail ID	
11.	Whether possessing any experience in handling insolvency matters in the Courts of Delhi? **(If Yes, please attach relevant document in support thereof)**.	

(Signature of Applicant)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

F. No. 6/12/2018-Judl/jtsecylaw/ 820-830 Dated: 02.07.2024

To,

The Pr. District & Sessions Judge (South-East), Saket District Court, Press Enclave Marg, Sector-6, Saket, New Delhi-110017	The Pr. District & Sessions Judge (South), Saket District Court, Press Enclave Marg, Sector-6, Saket, New Delhi-110017	The Pr. District & Sessions Judge (HQ), Tis Hazari Court Complex, Delhi-110054
The Pr. District & Sessions Judge (West), Tis Hazari Court Complex, Delhi-110054	The Pr. District & Sessions Judge (East), Karkardooma Court Complex, Delhi-110032	The Pr. District & Sessions Judge (Shahdara), Karkardooma Court Complex, Delhi-110032
The Pr. District & Sessions Judge (North-East), Karkardooma Court Complex, Delhi-110032	The Pr. District & Sessions Judge (South-West), Dwarka Court Complex, Delhi-110075	The Pr. District & Sessions Judge (North), Rohini Court Complex, Delhi-110085
The Pr. District & Sessions Judge (North-West), Rohini Court Complex, Delhi-110085	The Pr. District & Sessions Judge (New Delhi), Patiala House Court Complex, Delhi-110003	

Sub: Appointment of Official Receiver u/s 57 of the Provincial Insolvency Act, 1920.

Respected Sir/ Madam,

Please find attached herewith a copy of gazette notification dated 14.06.2024 pertaining to "Appointment of Official Receivers for National Capital Territory of Delhi Rules, 2024."

In this regard, it is requested to recommend a panel of 05 (Five) advocates for selecting one of them as Official Receivers from your district latest by 15th July, 2024.

Yours sincerely,

01/07/2024

(Bharat Parashar)
Pr. Secretary (Law, Justice & LA)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21062024-254745
SG-DL-E-21062024-254745

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 71
No. 154] DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946 [N. C. T. D. No. 71

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 जून, 2024

फा. सं. 6/12/2018–न्यायिक/jtsecylaw /735-744.—प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (2020 का अधिनियम V) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा आधिकारिक प्राप्तकर्ताओं की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

अध्याय–I
प्रारंभिक

1. **शीर्षक, प्रारंभ और प्रयोजनीयता**:– (1) इन नियमों को प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का अधिनियम V) की धारा 57 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए आधिकारिक प्राप्तकर्ता की नियुक्ति नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर लागू होंगे।

(3) वे दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन कीतिथि से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ**:– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) **''अधिनियम''** का अभिप्राय प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 (1920 का अधिनियम V) से है;

(ख) ''अधिवक्ता'' का अभिप्राय दिल्ली की विधिज्ञ परिशद के साथ पंजीकृत अधिवक्ता से है;

(ग) **''जिला''** का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में न्यायिक जिला से है;

(घ) **''जिला न्यायाधीश''** का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रत्येक न्यायिक जिले के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से होगा;

(ड़) **''विभाग''** का अभिप्राय है विधि न्याय और विधायी कार्य विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है;

(च) **''सरकार''** का अभिप्राय भारत के संविधान के अनुच्छेद 239–एए के साथ पठित अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल से है;

(झ) **''आधिकारिक प्राप्तकर्ता''** का अभिप्राय इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त आधिकारिक प्राप्तकर्ता से है;

(ज) **''पंजीकरण संख्या''** का अभिप्राय विभाग द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर के अनुसार नियुक्त आधिकारिक प्राप्तकर्ता को आवंटित पंजीकरण संख्या से है।

(2) कोई भी शब्द या अभिव्यक्ति जो इन नियमों में दिखाई देती है, लेकिन परिभाषित नहीं है, उसका वही अर्थ होगा जो अधिनियम के अन्तर्गत दिया जाना है।

(3) इन नियमों में आने वाले शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों या अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 की संख्या X) के अन्तर्गत दिया गया है।

(4) किसी भी अस्पष्टता के मामले में, विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई व्याख्या अंतिम होगी।

अध्याय–II

आधिकारिक प्राप्तकर्ता की नियुक्ति

3. **आधिकारिक प्राप्तकर्ता के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता आर योग्यताएँः** –(1) दिल्ली के न्यायालयों में अभ्यास करने वाला अधिवक्ता, जिसका विधिज्ञ में 15 साल से अधिक का कार्यकाल है तथा दिल्ली की न्यायालयों में दिवालिया मामलों को संभालने का अनुभव है, आधिकारिक प्राप्तकर्ता के रूप में नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए पात्र होगा।

4. **आधिकारिक प्राप्तकर्ता की रिक्तियों की संख्याः**– (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रत्येक जिले के लिए एक आधिकारिक प्राप्तकर्ता नियुक्त किया जा सकता है।

5. **नियुक्ति का तरीकाः**– (1) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विभाग द्वारा मांगे जाने पर, अपने अधिकार क्षेत्र में अभ्यास करने वाले पॉच अधिवक्ताओं के नाम, जिनके पास नियम 3 के अन्तर्गत निर्धारित अनुभव है, उनके द्वारा उचित समझी जाने वाली प्रक्रिया का पालन करने के बाद विभाग को विचार के लिए अनुशंसा करेंगे। .

(2) उप सचिव स्तर या उससे ऊपर के दो अधिकारियों और प्रधान सचिव (कानून, न्याय और विधायी मामले) की अध्यक्षता वाली समिति, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय द्वारा अनुशंसित नामों पर विचार करेगी तथा उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करना, जो आधिकारिक प्राप्तकर्ता के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त और उचित समझे जाएं।

(3) सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम 5(2) के अन्तर्गत समिति द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रत्येक जिले के लिए आधिकारिक प्राप्तकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकती है।

(4) सरकार, एक आदेश के माध्यम से, एक जिले के आधिकारिक प्राप्तकर्ता को एक से अधिक जिलों के लिए आधिकारिक प्राप्तकर्ता का भी निर्देश दे सकती है।

(5) आधिकारिक प्राप्तकर्ता का कार्यकाल तीन वर्षों के लिए होगा जिसे सरकार द्वारा उसके प्रदर्शन पर विचार करने के पश्चात एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

अध्याय–III

पारिश्रमिक

6. **आधिकारिक प्राप्तकर्ता को देय पारिश्रमिकः** –1. प्रत्येक आधिकारिक प्राप्तकर्ता को निम्नलिखित पारिश्रमिक प्राप्त होगाः–

	विवरण	प्रतिशत	टिप्पणियां
	1.	2.	3.
(क)	दिवालिया परिसंपत्ति से प्राप्त राशि पर	10,000/–रुपये प्रति परिसंपत्ति तक वसूली का 8 प्रतिशत और उससे अधिक 5 प्रतिशत	
(ख)	एक लेनदार द्वारा दिवाला न्यायाधीश को लिखित रूप में एक आवेदन प्राप्त होता है, जो दिवालिया की संपत्ति के किसी भी हिस्से को सुरक्षा के रूप में	10,000/–रुपये प्रति परिसंपत्ति तक वसूली का 8 प्रतिशत और उससे अधिक 5 प्रतिशत	

	6 प्रतिशत से अधिक रखता है, आधिकारिक प्राप्तकर्ता ने संपत्ति बेच दी है और बिक्री की आय पर न्यायालीय के एक लिखित आदेश के अन्तर्गत सुरक्षा प्राप्त कर ली है।		
(ग)	जहां दिवालिया के साथ समझौता हो गया हो या लेनदारों के बीच समाधान हो गया हो	10,000/–रुपये प्रति परिसंपत्ति तक, कुल राशि का 8 प्रतिशत लेनदारों को भुगतान करने पर सहमति हुई और उससे अधिक 5 प्रतिशत	
(घ)	जहां संपत्ति दूसरे जिले के आधिकारिक प्राप्तकर्ता के माध्यम से बेची जाती है, जहां संपत्ति स्थित है	10,000/–रुपये प्रति परिसंपत्ति तक, बिक्री का 5 प्रतिशत और उससे अधिक 4 प्रतिशत	
(ड़)	जहां आधिकारिक प्राप्तकर्ता ऐसी संपत्ति को बेचता है जो दूसरे जिले में दिवालियापन की कार्यवाही के अधीन है	10,000/–रुपये तक बिक्री की आय का 3 प्रतिशत और उससे अधिक 2 प्रतिशत	
(च)	जहां नजारत स्टाफ के माध्यम से दिवालिया की संपत्ति बेची जाती है	5,000/–रुपये प्रति परिसंपत्ति तक बिक्री की आय का 5 प्रतिशत और उससे अधिक 3 प्रतिशत	
	टीप– बिक्री आय का दो प्रतिशत ''XVII–न्याय विविध प्रशासन शुल्क और जुर्माना – दिवालियापन न्यायालयों की रसीदें'' शीर्षक के अन्तर्गत सरकार को जमा किया जाएगा।		
(छ)	जहां संपत्ति दूसरे राज्य के न्यायालय के माध्यम से बेची जाती है जहां संपत्ति स्थित है	10,000/–रुपये तक बिक्री की आय का 5 प्रतिशत और उससे अधिक 2 प्रतिशत	
(ज)	जहां आधिकारिक प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में दिवालिया घोषित किसी दिवालिया की संपत्ति बेचता है	10,000/–रुपये तक बिक्री की आय का 3 प्रतिशत और उससे अधिक 2 प्रतिशत	
(झ)	जहां आधिकारिक प्राप्तकर्ता द्वारा संपत्ति के मूल्य की कोई वसूली किए जाने से पहले न्यायनिर्णयन के आदेश को रद्द कर दिया जाता है	संपत्ति के अनुमानित मूल्य का 1 प्रतिशत	
(ञ)	जहां आधिकारिक प्राप्तकर्ता दिवाला कार्यवाही में निर्णय से पहले एक अंतरिम प्राप्तकर्ता है	उपर्युक्तानुसार	
(ट)	निर्णय से पहले न्यायालय के माध्यम से की गई बिक्री के कारण नाजिर से आधिकारिक प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त धन के मामले में	10,000/–रुपये तक प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत और उससे अधिक 3 प्रतिशत	

बशर्ते कि पारिश्रमिक की आधी राशि मद (ङ), (ज), (झ) और (ञ) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, सभी मामलों में आधिकारिक प्राप्तकर्ता को तब तक भुगतान नहीं की जा सकती जब तक कि परिसंपत्ति वितरित नहीं हो जाती।

2. भुगतान प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 57 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत या अन्यथा प्रदान की गई निधि से किया जाएगा।

7. **गिरवी के अधीन संपत्ति की बिक्री पर कमीशनः** – (1) किसी लेनदार के पास गिरवी रखी गई संपत्ति के मामले में, संपूर्ण बिक्री–आय पर कमीशन केवल तभी लिया जाना चाहिए, जब लेनदार न्यायालय के माध्यम से प्रतिभूति की वसूली के लिए लिखित आवेदन करता है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि क्रय राशि गिरवी धन से अधिक है या नहीं। ऐसे मामलों में, जहां ऐसी संपत्ति सुरक्षित लेनदार द्वारा इस प्रकार के किसी भी आवेदन के बिना विक्रयकी जाती है, तो बिक्री आय पर ऋणभार से जुड़ी राशि को घटाकर कमीशन लिया जाना चाहिए।

टीपः– आधिकारिक प्राप्तकर्ता को संपत्ति के निपटान में तब तक देरी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह सुरक्षित लेनदारों को संपत्ति में उनके हित की बिक्री हेतु उनकी सहमति देने के लिए प्रेरित न कर सके। निस्संदेह, यह सहमति प्राप्त करना और इस प्रकार संपत्ति को सभी ऋणभारों से मुक्त करके बेचना उपयोगी हो सकता है; लेकिन मामले में अत्यधिक देरी नहीं होनी चाहिए। आधिकारिक प्राप्तकर्ता मोचन की इक्विटी का निपटान करने के लिए हर समय सक्षम है जो वास्तव में वह सब कुछ है, जो उसमें निहित है।

अध्याय–IV

''आधिकारिक प्राप्तकर्ता पारिश्रमिक निधि''

8. **प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 57(3) के अन्तर्गत प्रदान की गई निधि** :– (1) जिला न्यायाधीश द्वारा खाता खोला जाएगा।

(2) एक आधिकारिक प्राप्तकर्ता की सेवाओं के संबंध में प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 की धारा 56 की उप–धारा (2) के खंड (ख) के अन्तर्गत देय समस्त धनराशि ''आधिकारिक प्राप्तकर्ता पारिश्रमिक निधि'' शीर्षक के अंतर्गत दिवाला न्यायाधीश के नाम पर जिला कोषागार या उप–कोषागार में जमा की जाएगी।

अध्याय–V

आधिकारिक प्राप्तकर्ता द्वारा व्यापार का लेन–देन

9. **आधिकारिक प्राप्तकर्ता द्वारा व्यापार का लेनदेन** :–(1) आधिकारिक प्राप्तकर्ता को प्रत्येक मामले के लिए एक अलग रिकॉर्ड रखना चाहिए जिसमें विस्तार से दर्शाया जाए कि प्रत्येक दिन क्या कार्रवाई की गई; ताकि संपूर्ण कार्यवाही का निरंतर विवरण उपलब्ध कराया जा सके। वह विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा या न्यायालय द्वारा, जब भी आवश्यक हो, ऐसे रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा।

(2) आधिकारिक प्राप्तकर्तास्वयं द्वारा निपटाए गए मामलों के मासिक विवरण को भी विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग को प्रस्तुत करेगा।

रिकॉर्ड को दो भागों में अनुरक्षित किया जाना चाहिए – भाग क–प्रांतीय दिवाला अधिनियम की धारा 80 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु, भाग ख–अन्य सभी कार्यवाहियों हेतु।

12. आधिकारिक प्राप्तकर्ताओं के रिकॉर्ड और रजिस्टर जब पूर्ण हो जाएं तो उन्हें न्यायालय के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए न्यायालय को सौंप दिया जाना चाहिए और विभाग का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् उनके साथ रिकॉर्ड कक्ष में भेज दिया जाना चाहिए।

अध्याय–VI

आधिकारिक प्राप्तकर्ता की मुहर

10. **आधिकारिक प्राप्तकर्ता की मुहर** :– (1) प्रत्येक आधिकारिक प्राप्तकर्ता 5 सेमी व्यास की एक सादे गोलाकार मुहर का उपयोग करेगा जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, जिसमें उसका नाम, उस क्षेत्र का नाम जिसमें उसे अपने कार्यों का निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया है, पंजीकरण संख्या तथा परिधि निर्धारण ''आधिकारिक प्राप्तकर्ता'' के साथ–साथ उस जिले का नाम जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है और सरकार का नाम, जिसने उसे नियुक्त किया है, अंकित होगा।

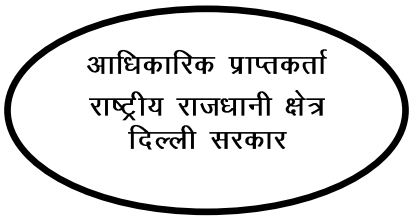

अध्याय–VII

पेशेवर या अन्य कदाचार

11. **आधिकारिक प्राप्तकर्ता द्वारा पेशेवर या अन्य कदाचार के आरोपों की जांचः**– (1) किसी आधिकारिक प्राप्तकर्ता के कदाचार के किसी भी कृत्य की जांच विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग द्वारा स्वतः संज्ञान या इस संबंध में प्राप्त शिकायत पर आरंभ की जा सकती है।

(2) आधिकारिक प्राप्तकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विधि, न्याय और विधायी कार्य विभाग द्वारा ऐसे आधिकारिक प्राप्तकर्ता के विरूद्ध उचित कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है, जिसमें कदाचार की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार, राशि की वसूली या/उसे पदच्युत करने या लिखित चेतावनी के द्वारा, जैसा भी मामला हो, भाामिल है।

(3) पदच्युत के मामले में, अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में जारी की जा सकती है जिसे संबंधित अधिकारी तथा दिल्ली विधिज्ञ परिशद् को सूचित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनमीत सिंह वालिया, संयुक्त सचिव

DEPATMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 14th June, 2024

No. F.6/12/2018-Judicial/jtsecylaw /735-744.—In exercise of the powers conferred by section 57 of the Provincial Insolvency Act, 1920 (Act V of 2020), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules for appointment of Official Receivers, namely,

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Title, Commencement and Applicability. –(1) These Rules shall be called the appointment of Official Receivers for National Capital Territory of Delhi Rules, 2024 under section 57 of the Provincial Insolvency Act, 1920 (Act V of 1920).

(2) These shall be applicable within the National Capital Territory of Delhi.

(3) They shall come into force on the date of publication of this notification in the Delhi Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Provincial Insolvency Act, 1920 (Act V of 1920)

(b) "Advocate" means an Advocate registered with Bar Council of Delhi.

(c) "District" means Judicial District in National Capital Territory of Delhi.

(d) "District Judge" shall mean the Principal District & Session Judge as appointed by High Court of Delhi for each Judicial District in National Capital Territory of Delhi.

(e) "Department" means Department of Law Justice and Legislative Affairs, Government of National Capital Territory of Delhi.

(f) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under the Article 239 read with Article 239-AA of the Constitution of India.

(g) "Official Receiver" means Official Receiver appointed under these Rules.

(h)" Registration number" means the registration number allotted to Official Receiver so appointed, as per the register maintained by the Department.

(2) Any word or expressions appearing in these rules, but not defined shall have the same meaning as assigned to be given and under the Act.

(3) The words and expressions appearing in these rules, but not defined under these rules or the Act, shall have the meaning as given to them under the General Clauses Act, 1897 (No. X of 1897).

(4) In case of any ambiguity, the interpretation provided by the Department shall be final.

CHAPTER-II

APPOINTMENT OF OFFICIAL RECEIVER

3. Eligibility and Qualifications for appointment as Official Receiver. –(1) An Advocate practising in the Courts of Delhi having standing of more than 15 years at Bar and having experience in handling insolvency matters in the Courts of Delhi, shall be eligible to be considered for appointment as Official Receiver.

4. Number of vacancies of Official Receiver. – (1) One Official Receiver may be appointed for each judicial district of National Capital Territory of Delhi.

5. Manner of Appointment. – (1) Principal District and Session Judge, upon requisition by the Department, shall recommend names of five advocates practising in their jurisdiction, having experience as prescribed under Rule 3, after following such procedure as deemed appropriate by them, to the Department for consideration.

(2) The Committee comprising two officers of Deputy Secretary level or above and headed by Principal Secretary (Law, Justice and Legislative Affairs) shall consider the names recommended by the Office of Ld. Principal District and Session Judge and recommend suitable candidates, as deemed fit and proper for discharging the duties of Official Receiver.

(3) The Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a person as may be deemed suitable by the Committee under Rule 5(2) as Official Receiver for each District of National Capital Territory of Delhi.

(4) The Government may, by way of an order, also direct Official Receiver of a district to be Official Receiver for more than one district.

(5) The tenure of the Official Receiver shall be for three years which may be extended for oneyearby the Government after due consideration of his performance.

CHAPTER-III

REMUNERATION

6. Remuneration payable to the Official Receiver. –1. Every Official Receiver shall receivethe following remuneration:-

	Description	Percentage	REMARKS
	1	2	3
(a)	On amount realized from the insolvents assets	8 per cent of the realization up to Rs 10,000 per estate and beyond that 5 per cent	
(b)	When an application is received in writing to the insolvency Judge by a creditor who holds and beyond that 6 per cent as security any part of the insolvent's property, the Official Receiver has sold the property and realized security under a written order of the court, on the proceeds of sale	8 per cent of the realization, up to Rs 10,000 per estate and beyond that 5 per cent	
(c)	Where a compromise has been effected with the in- solvent or settlement made among the creditors	8 per cent of the total sum, agreed to be paid to the creditors up to Rs 10,000 per estate and beyond that 5 per cent	
(d)	Where the property is sold through the Official Receiver of another district where the property is situated	5 per cent of the sale proceeds up to Rs 10,000 per estate and beyond that 4per cent	
(e)	Where the Official Receiver sells property which is subject of insolvency proceedings in another district	3 per cent of the sale proceeds up to Rs 10,000 and beyond that 2 per cent	
(f)	Where the property of the Insolvent is sold through the Nazarat Staff	5 per cent of the sale proceeds up to Rs.5,000 per estate and beyond that 3 per cent	
	Note- Two per cent of the sale proceeds shall be credited to Government under the head "XVII-Administration of Justice Misc. Fees and Fines – insolvency Courts Receipts"		
(g)	Where the property is sold through a Court of another State where the property is situate	5 per cent of the sale proceeds- up to Rs 10,000 per estate and beyond that 2 per cent	
(h)	Where the Official Receiver sells property of an insolvent adjudicated in another State	3 per cent of the sale proceeds up to Rs 10,000 and beyond that 2 per cent	
(i)	Where the order of adjudication is set aside before the value of the property Official Receiver has made any realization	1 per cent of the estimated value of the property	
(j)	Where the Official Receiver is an *Ad interim* Receiver prior to adjudication in Insolvency Proceedings	Same as above	
(k)	In the case of money received by the Official Receiver from the Nazir on account of sales held through Court prior to adjudication	5 per cent of the amount received up to Rs 10,000 and beyond that 3 per cent	

Provided that in all cases except those mentioned in items (e), (h),(i) and (j) half the amount of remuneration may not be paid to the Official Receiver until the assets are distributed.

2. The payment would be made out of the Fund provided under sub-section (3) of section 57 of the Provincial Insolvency Act, 1920, or other- wise.

7. Commission on sale of property subject to mortgage. – (1) In the case of property mortgaged to a creditor, commission should be charged on the entire sale-proceeds only if the creditor makes a written application for the

realization of the security through the Court irrespective of the fact whether the purchase money exceeds the mortgage money or not. In cases, where such property is sold without any such application by the secured creditor, the commission should be charged on the sale proceed less the amount involved by the encumbrance.

Note.-The Official Receiver must not delay the disposal of property till such time as he can induce the secured creditors to give their consent to the sale of their interest also in the property. It may be useful, of course, to obtain this consent and so to sell the property free of all encumbrances but the matter must not bedelayed too long. The Official Receiver is competent at all times to dispose of the equity of redemption which in fact is all that does vest in him.

CHAPTER-IV

"OFFICIAL RECEIVER'S REMUNERATION FUND"

8. Funds provided under section 57(3) of the Provincial Insolvency Act. – (1)An account shall be opened by the District Judge.

(2) All sums payable under clause (b) of sub-section (2) of section 56 of the Provincial Insolvency Act, 1920 in respect of the services of an Official Receiver shall be credited into the District Treasury or a Sub-Treasury in the name of the Insolvency Judge, under the head "Official Receiver's Remuneration Fund"

CHAPTER-V

TRANSACTION OF BUSINESS BY OFFICIAL RECEIVER

9. Transaction of Business by Official Receiver.–(1) The Official Receiver should maintain a separate record for each case showing in detail what action was taken on each day so as to provide a continuous history of the whole proceeding. He shall produce such register as and when required by the authorized officer of Department of Law, Justice & Legislative Affairs or by the Court.

(2) The Official Receiver shall also submit a monthly statement of cases dealt by him to the Department of Law, Justice & Legislative Affairs.

The record should be maintained in two parts—Part A for proceedings under section 80 of the Provincial Insolvency Act, Part B for all other proceedings.

12. The records and registers of the Official Receivers when complete should be made over to the Court for being made a part of the Court Records and being consigned to the Record Room along with them after obtaining approval of the Department.

CHAPTER-VI

SEAL OF OFFICIAL RECEIVER

10. Seal of Official Receiver. – (1) Every Official Receiver shall use a plain circular seal of a diameter of 5cm as indicated by a drawing given below, bearing his name, the name of the area within which he has been appointed to exercise his functions, the registration number and circumscription “OFFICIAL RECEIVER”along with name of the District for which he has been appointedfor and the name of the Government, which has appointed him.

CHAPTER-VII

PROFESSIONAL OR OTHER MISCONDUCT

11. Enquiry into allegations of professional or other misconduct by Official Receiver. – (1) An enquiry into any act of misconduct of a Official Receiver may be initiated by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs suomoto or on complaint received in this regard.

(2) After affording an opportunity of being heard to the Official Receiver, appropriate action can be recommended by the Department of Law, Justice & Legislative Affairs against such Official Receiver, including recovery of amount or/ his removal from the post or by way of written warning, as the case may be, according to the nature and gravity of the misconduct.

(3) In case of removal, the notification may be issued in the Official Gazette which shall be communicated to the official concerned and the Bar Council of Delhi.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MANMEET SINGH WALIA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.06.21 10:48:16 +05'30'